आवास विभाग लाएगी फ्रीहोल्ड नीति, सॉफ्टवेयर ठीक करेगा पावर कॉर्पोरेशन

आईआईडीसी ने उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए दिए निर्देश, इन्वेस्ट यूपी की पहली बैठक में उद्यमियों की कई समस्याओं का समाधान

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। आवास विभाग आने वाले दिनों में फ्रीहोल्ड नीति लाएगा और पावर कॉर्पोरेशन उद्योगों की अधिक बिल की समस्या का समाधान करेगा। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) आलोक टंडन की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को संपन्न इन्वेस्ट यूपी की पहली बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

लोकभवन में वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) की ओर से इंप्रूवमेंट ट्रस्ट/लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखंडों के फ्रीहोल्ड का मामला उठाया गया। अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा आवंटित भूखंडों के समाप्त पट्टे की भूमि को फ्री होल्ड करने के लिए आवास विभाग को नीति का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। वहीं, आईआईडीसी टंडन ने पावर कॉर्पोरेशन को निर्देशित किया कि नीलामी में खरीदी गई रुग्ण इकाइयों का विद्युत बकाया पुरानी इकाई से ही वसूला जाए न कि खरीददार से। मासिक विद्युत बिल अधिक आने के प्रकरण में पावर कॉर्पोरेशन की ओर से बताया गया कि बिलिंग सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव कर उद्योगों की कुछ श्रेणियों की इस समस्या का तकनीकी समाधान अक्तूबर तक कर दिया जाएगा। आईआईडीसी ने कहा कि औद्यागिक विकास सरकार की उच्चतम प्राथमिकताओं में है। पूर्व के उद्योग बंधु की तरह इंवेस्ट यूपी इसी तरह का संवाद आगे भी जारी रखेगा।

बैठक में 25 उद्योगपतियों व औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें 21 मामलों का निस्तारण किया गया। वहीं, राजस्व विभाग के भू-उपयोग परिवर्तन से संबंधित छह मामलों पर अलग से विचार-विमर्श हुआ। उद्योगों के लिए भूमि विनिमय, भू-उपयोग परिवर्तन, चकरोड, नाली आदि से संबंधित इन मामलों का समाधान कर सक्षम स्तर पर मंजूरी के लिए भेजा गया। बैठक में अपर मुख्य सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल, सीईओ इन्वेस्ट यूपी नीना शर्मा, सीईओ यूपीसीडा मयूर माहेश्वरी व औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

प्रदेश में 17 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव

लखनऊ। प्रदेश में बनाए गए एक्सप्रेस-वे व प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे के आसपास 17 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी है। इनमें कई औद्योगिक क्षेत्रों का विकास निजी सेक्टर के सहयोग से किए जाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बनाए गए एक्सप्रेस-वे व प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक विकास के लिए लैंड बैंक विकसित करने से संबंधित कार्ययोजना तैयार करने के लिए अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति ने प्रदेश के जिलाधिकारियों से एक्सप्रेस-वे पर स्थित उच्च संभावना वाले क्षेत्रों को चिह्नित कर रिपोर्ट मांगी थी। अब तक 23 जिलों के डीएम की रिपोर्ट मिली है। इसमें 15 जिलों में 8380 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई है। इनमें गोरखपुर में प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारा भी शामिल है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) मथुरा में राया तथा अलीगढ़ में टप्पल बाजना में शहरी नोड्स स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। इस तरह 17 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव है। अन्य जिलों से रिपोर्ट आने पर प्रस्तावित नए औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या बढ़ सकती है।

15 जिलों में 8380 हेक्टेयर जमीन चिह्नित, प्रस्तावित पार्कों की संख्या बढ़ेगी